गुरुवार, 16 जुलाई,2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर स्पेन से खिताबी मुकाबला पक्का किया

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

अगले साल आएगी सलमान की फिल्म

Page-05

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

2.19 लाख करोड़ रुपये के सात मेगा प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

- **केंद्रीय कैबिनेट ने सेमीकॉन 2.0, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं समेत कुल 2.19 लाख करोड़ रुपये की सात बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी।**
- **कैबिनेट ने गंगा और वरुण नदी के किनारे 89 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड नेटवर्क को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य वाराणसी में ट्रैफिक जाम कम करना, कनेक्टिविटी बेहतर बनाना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है।**

केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे, तकनीकी विकास और औद्योगिक उत्पादन को नई गति देने के उद्देश्य से 2.19 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन फैसलों को आने वाले वर्षों के आर्थिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाना है।कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने वाली नई योजना, यूरिया-2026 से जुड़ी राष्ट्रीय निवेश नीति तथा रेलवे और सड़क क्षेत्र की कई बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से देश में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारत की उत्पादन क्षमता को मजबूती मिलेगी।बैठक में वाराणसी के लिए दो बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी गई। इनमें गंगा नदी के किनारे लगभग 14,448 करोड़ रुपये की लागत से छह लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर और वरुण नदी के किनारे करीब 10,998 करोड़ रुपये की लागत से चार एवं छह लेन का कॉरिडोर बनाया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक जाम कम करना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है।सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम के तहत सरकार घरेलू चिप निर्माण उद्योग को मजबूत करना चाहती है ताकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके। वहीं मोबाइल निर्माण क्षेत्र में नई नीति से विदेशी निवेश आकर्षित होने और निर्यात बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि ये सभी फैसले भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि विपक्ष ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन, लागत और समय-सीमा को लेकर सवाल उठाए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इन परियोजनाओं को जमीन पर कितनी तेजी से उतारा जाता है और इनका लाभ आम जनता तक कब पहुंचता है।

मानसून सत्र से पहले शरद पवार का बड़ा संकेत

संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले राष्ट्रीय राजनीति में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी (शरदचंद्र पवार) केंद्र सरकार के दो महत्वपूर्ण विधेयकों—महिला आरक्षण और परिसीमन बिल—का समर्थन कर सकती है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल होने की संभावना से इनकार किया जा रहा है, लेकिन संसद में इन विधेयकों के पक्ष में मतदान करने की चर्चा ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है।बताया जा रहा है कि पार्टी इन दोनों मुद्दों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर मानते हुए अपना रुख तय कर रही है। महिला आरक्षण को लंबे समय से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जाता रहा है। वहीं परिसीमन प्रक्रिया भविष्य में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करने से जुड़ी है, जिसका असर कई राज्यों के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि शरद पवार गुट इन विधेयकों का समर्थन करता है तो यह विपक्षी एकता के लिए चुनौती बन सकता है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि किसी विधेयक का समर्थन करने का मतलब एनडीए में शामिल होना नहीं है।

तत्काल मेडिकल सहायता की मांग

सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची याचिका

प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि लगातार उपवास के कारण उनकी तबीयत बिगड़ रही है और यदि समय रहते उचित इलाज नहीं मिला तो स्थिति गंभीर हो सकती है।जानकारी के अनुसार वांगचुक राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदर्शन का संबंध कथित नीट परीक्षा गड़बड़ियों और उससे जुड़े मुद्दों से बताया जा रहा है। इस बीच अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है।याचिका में कहा गया है कि डॉक्टरों की निगरानी में सोनम वांगचुक की नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें लिक्विड डाइट तथा अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी होती रहे ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।मामले के सामने आने के बाद सामाजिक संगठनों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन प्रदर्शनकारी के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है और कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

(यूबीटी) बनाम शिंदे गुट,छह सांसदों को कानूनी नोटिस

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना के दो धड़ों के बीच टकराव तेज हो गया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने अपने छह बागी लोकसभा सांसदों को कानूनी नोटिस जारी कर सख्त संदेश दिया है। पार्टी का दावा है कि इन सांसदों का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में विलय संविधान और दल-बदल कानून के तहत वैध नहीं माना जा सकता। ऐसे में यदि सांसद पार्टी लाइन से हटकर कोई कदम उठाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।शिवसेना (यूबीटी) के संसदीय दल के नेता अरविंद सावंत ने 13 जुलाई को भेजे गए नोटिस में सभी सांसदों को याद दिलाया कि उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में और पार्टी के अधिकृत चुनाव चिन्ह पर लड़ा था। चुनाव के दौरान उन्होंने शिंदे गुट का खुलकर विरोध किया था और जनता से उसी आधार पर वोट मांगे थे। इसलिए अब किसी दूसरे गुट में शामिल होने का दावा करना मतदाताओं के विश्वास के साथ धोखा होगा।दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन नोटिसों को पूरी तरह राजनीतिक कदम बताते हुए खारिज कर दिया। उनका कहना है कि नोटिस भेजने से किसी सांसद की राजनीतिक स्थिति नहीं बदलती और यह केवल दबाव बनाने की कोशिश है। शिंदे गुट का दावा है कि उनके साथ आने वाले जनप्रतिनिधि अपनी राजनीतिक इच्छा से फैसले ले रहे हैं और उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है।

वाराणसी को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत,₹25,446 करोड़ के एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी के बुनियादी ढांचे को नई पहचान देने वाले एक महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत गंगा और वरुण नदी के किनारे करीब 89 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 25,446 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। सरकार का दावा है कि इसके पूरा होने के बाद वाराणसी को वर्षों से परेशान कर रही ट्रैफिक जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलेगी और शहर का यातायात अधिक तेज, सुरक्षित और व्यवस्थित होगा।सरकार के अनुसार यह परियोजना आधुनिक 'हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल' यानी HAM के तहत विकसित की जाएगी। इस मॉडल में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी रहती है, जिससे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लागत को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। प्रस्ताव के मुताबिक गंगा नदी के किनारे छह लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जबकि वरुण नदी के किनारे चार और छह लेन वाले आधुनिक मार्ग विकसित किए जाएंगे। इन सड़कों के जरिए शहर के विभिन्न हिस्सों को सीधे जोड़ा जाएगा, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाकों पर दबाव कम होगा।परियोजना का एक बड़ा उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। वाराणसी हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का स्वागत करता है। काशी विश्वनाथ धाम, घाटों और अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में लगने वाला समय इस परियोजना के बाद काफी कम होने की उम्मीद है। इसके साथ ही माल परिवहन और स्थानीय व्यापार को भी गति मिलेगी, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है।

जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले ओडिशा में रेड अलर्ट

ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से ठीक पहले मौसम ने प्रशासन और श्रद्धालुओं दोनों की चिंता बढ़ा दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। पुरी समेत कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जहां गुरुवार को लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।आईएमडी के अनुसार उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट के पास बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश का प्रभाव तेजी से बढ़ सकता है। इसके चलते कई जिलों में तेज हवाएं, जलभराव और स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।रथ यात्रा को देखते हुए राज्य सरकार ने व्यापक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में राहत एवं बचाव दलों की तैनाती बढ़ा दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल की टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेडिकल कैंप, कंट्रोल रूम और आपातकालीन सेवाओं को भी सक्रिय कर दिया गया है।पुरी जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की गई है। लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए जा सकते हैं।

यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले कई शहरों में तबाही; पश्चिमी देशों ने बढ़ाई सैन्य सहायता

इन हमलों के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस सहित कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। अमेरिका ने कहा कि वह यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमता को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सैन्य सहायता देने पर काम कर रहा है। वहीं यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की संभावना पर चर्चा शुरू कर दी है। नाटो महासचिव ने कहा कि गठबंधन यूक्रेन की सुरक्षा के लिए आवश्यक सहयोग जारी रखेगा।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है।।15 जुलाई को रूस ने यूक्रेन के कई प्रमुख शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार राजधानी कीव, खारकीव, ओडेसा और इनीप्रो सहित कई इलाकों में देर रात विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। हमलों के कारण कई आवासीय इमारतों, ऊर्जा सुविधाओं और सार्वजनिक ढांचों को नुकसान पहुंचा। कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई, जबकि राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चला रहे हैं।यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया कि रूस ने बड़ी संख्या में ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें दागीं, जिनमें से अधिकांश को वायु रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। हालांकि कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहीं, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति और आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुईं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि रूस लगातार नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर और सख्त कदम उठाने चाहिए।दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके हमले केवल सैन्य ठिकानों और रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर किए गए। रूस का दावा है कि यूक्रेन के सैन्य बुनियादी ढांचे और हथियार भंडारण केंद्रों को नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि स्वतंत्र एजेंसियां दोनों पक्षों के दावों की पूरी तरह पुष्टि नहीं कर सकी हैं।इन हमलों के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस सहित कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। अमेरिका ने कहा कि वह यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमता को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सैन्य सहायता देने पर काम कर रहा है। वहीं यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की संभावना पर चर्चा शुरू कर दी है। नाटो महासचिव ने कहा कि गठबंधन यूक्रेन की सुरक्षा के लिए आवश्यक सहयोग जारी रखेगा। युद्ध का असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है। लगातार बढ़ते संघर्ष से वैश्विक ऊर्जा बाजार, खाद्यान्न आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी दबाव बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में हमलों की तीव्रता इसी तरह बढ़ती रही, तो यूरोप की सुरक्षा स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है।फिलहाल रूस और यूक्रेन दोनों अपने-अपने सैन्य अभियानों को जारी रखे हुए हैं। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच युद्धविराम की दिशा में कोई नई पहल होती है या फिर यह संघर्ष आने वाले दिनों में और व्यापक रूप लेता है।

ताइवान के आसपास चीनी सैन्य गतिविधियां तेज; इंडो-पैसिफिक में बढ़ी चिंता

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन और ताइवान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। 15 जुलाई को ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों के दौरान बड़ी संख्या में चीनी सैन्य विमान और नौसैनिक पोत ताइवान के आसपास सक्रिय रहे। मंत्रालय के अनुसार, कई चीनी लड़ाकू विमान ताइवान जलडमरूमध्य की मध्य रेखा के करीब पहुंचे, जबकि कुछ विमान ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (ADIZ) में भी प्रवेश करते देखे गए। इसके बाद ताइवान की सेना ने अपने लड़ाकू विमानों, नौसैनिक जहाजों और वायु रक्षा प्रणालियों को तत्काल सक्रिय कर दिया।ताइवान सरकार ने कहा कि वह हर गतिविधि पर लगातार नजर रख रही है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रपति कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सहयोगी देशों के साथ लगातार संपर्क में है।दूसरी ओर, चीन ने अपनी सैन्य गतिविधियों को नियमित अभ्यास बताया है। बीजिंग का कहना है कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है। चीन ने एक बार फिर उन देशों को चेतावनी दी है जो ताइवान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि बाहरी हस्तक्षेप क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकता है।इस घटनाक्रम पर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने चिंता जताई है। अमेरिका ने कहा कि ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता वैश्विक व्यापार तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वॉशिंगटन ने सभी पक्षों से संयम बरतने और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से करने की अपील की है। वहीं जापान ने भी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर नजर बनाए रखने की बात कही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक मेंमहत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में देश की विनिर्माण क्षमता, बुनियादी ढांचे, कृषि, परिवहन और समुद्री क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इन निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम और वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। हम आपको बता दें कि कैबिनेट ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (एमपीएमएस) को 62,500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहने वाली इस योजना के तहत भारत में मोबाइल फोन निर्माण पर 2.25 से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। घरेलू स्तर पर प्रमुख कंपोनेंट्स की खरीद पर अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत और भारतीय ब्रांडों द्वारा डिजाइन एवं अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि योजना अवधि में लगभग 39 लाख करोड़ रुपये का मोबाइल उत्पादन होगा, निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा करीब 60 हजार प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। यह योजना पीएलआई योजना के बाद भारत को वैश्विक मोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में और मजबूत करेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को और गति देने के लिए सरकार ने सेमिकॉन 2.0 को भी 1.27 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी। यह कार्यक्रम चिप डिजाइन, मशीनों एवं कच्चे माल के निर्माण, नए फैब स्थापित करने, एटीएमपी/ओसैट इकाइयों के विस्तार, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा विकास जैसे छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगा।

युद्धविराम की कोशिशों के बीच इज़राइल के नए हमलेमानवीय संकट और गहराया

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

मध्य पूर्व में इज़राइल और हमास के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है।।15 जुलाई को गाजा पट्टी में एक बार फिर इज़राइली सेना ने कई इलाकों में सैन्य अभियान चलाया। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, हवाई हमलों और सैन्य कार्रवाई में कई लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि हजारों परिवार पहले से ही विस्थापन और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं।इज़राइली सेना का कहना है कि उसके अभियान का उद्देश्य हमास के ठिकानों, सुरंगों और हथियार भंडार को निशाना बनाना है। सेना के मुताबिक, हाल के दिनों में हमास की ओर से रॉकेट हमलों और सुरक्षा बलों पर हमलों की कोशिशें जारी रही हैं, जिसके जवाब में यह कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर हमास ने इज़राइल पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है।इस बीच कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत जारी है। राजनयिक सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच कुछ मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन स्थायी युद्धविराम को लेकर अब भी कई महत्वपूर्ण मतभेद बने हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि बातचीत को सफल बनाने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं और सभी पक्षों से लचीला रुख अपनाने की अपील की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियों ने गाजा की मानवीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को भोजन, स्वच्छ पानी, दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अस्पतालों की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि जल्द कोई व्यापक युद्धविराम समझौता नहीं होता, तो यह संघर्ष पूरे क्षेत्र की स्थिरता को और प्रभावित कर सकता है। फिलहाल दुनिया की नजर काहिरा और दोहा में चल रही वार्ताओं पर है। यदि बातचीत सफल होती है, तो हजारों नागरिकों को राहत मिल सकती है, लेकिन यदि समझौता नहीं हो पाया, तो गाजा में मानवीय संकट और गहरा होने की आशंका बनी हुई है।

अमेरिका ने रूस से तेल खरीद पर भारत समेत कई देशों को दी चेतावनी

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। 15 जुलाई को अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया कि यदि रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार कर बड़े पैमाने पर व्यापार जारी रहा, तो संबंधित देशों और कंपनियों के खिलाफ अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में हलचल तेज हो गई और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।अमेरिका का कहना है कि रूस की ऊर्जा बिक्री से होने वाली आय का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा रहा है। इसलिए मॉस्को पर आर्थिक दबाव बनाए रखना जरूरी है। इसी उद्देश्य से अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार प्रतिबंधों को प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे अपने साझेदार देशों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं ताकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुए बिना प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।भारत ने इस पूरे मुद्दे पर अपना पुराना रुख दोहराया है। भारत का कहना है कि देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। सरकार के अनुसार, भारत जहां से भी उचित कीमत पर कच्चा तेल उपलब्ध होगा, वहां

से खरीद जारी रखेगा। अधिकारियों का कहना है कि ऊर्जा आयात से जुड़े फैसले पूरी तरह आर्थिक जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करता है और किसी भी निर्णय में अपने रणनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगा।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से प्रतिबंधों को और सख्ती से लागू किया जाता है, तो वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। इसका असर एशियाई देशों की ऊर्जा लागत, परिवहन खर्च और महंगाई पर भी पड़ सकता है। वहीं तेल निर्यातक देशों की रणनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। फिलहाल दुनिया की नजर अमेरिका, रूस और प्रमुख तेल आयातक देशों के अगले कदम पर टिकी है। यदि इस मुद्दे पर तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, कूटनीतिक संबंधों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस विषय पर होने वाले फैसलों को पूरी दुनिया गंभीरता से देख रही है।

संपादक की कलम से

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर हमेशा से पड़ता रहा है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए वैश्विक कीमतों में बदलाव सीधे तौर पर देश की ऊर्जा लागत, महंगाई और आम नागरिकों की जेब पर प्रभाव डालता है। पिछले कुछ समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में अपेक्षित कमी नहीं आई। इसी मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि जब तेल सस्ता हो रहा है तो जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही।यह प्रश्न केवल राजनीति का नहीं, बल्कि आर्थिक नीति और जनहित का भी है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें केवल कच्चे तेल के भाव से तय नहीं होतीं। इनमें रिफाइनिंग लागत, परिवहन, विपणन खर्च, केंद्र और राज्य सरकारों के कर तथा विनिमय दर जैसे कई कारक शामिल होते हैं। इसके बावजूद यह भी उतना ही सत्य है कि आम नागरिक इन तकनीकी पहलुओं से अधिक अपनी जेब पर पड़ने वाले असर को महसूस करता है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि वैश्विक बाजार में तेल सस्ता हुआ है तो घरेलू बाजार में भी उसका लाभ दिखाई देना चाहिए।महंगाई आज भी देश के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है। परिवहन लागत बढ़ने से खाद्यान्न, फल-सब्जियों, दूध, निर्माण सामग्री और रोजमर्रा की लगभग हर वस्तु महंगी हो जाती है। इसका सबसे अधिक असर मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग और किसानों पर पड़ता है। ऐसे में यदि ईंधन की कीमतों में थोड़ी भी राहत मिलती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव व्यापक अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है।सरकार का पक्ष भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें स्थिर नहीं रहतीं। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति संबंधी अनिश्चितता और डॉलर की मजबूती जैसे कारण कभी भी कीमतों को फिर ऊपर ले जा सकते हैं। ऐसे में सरकार कई बार भविष्य के जोखिमों को देखते हुए तत्काल कीमतों में कटौती करने से बचती है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाला कर राजस्व सरकार की विकास योजनाओं और सार्वजनिक व्यय का भी महत्वपूर्ण स्रोत है।फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यदि सरकार कीमतों में कटौती नहीं कर सकती, तो उसे इसके आर्थिक कारण स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखने चाहिए। इससे अनावश्यक राजनीतिक विवाद कम होंगे और नागरिकों का विश्वास भी मजबूत होगा। दूसरी ओर विपक्ष की जिम्मेदारी भी केवल आरोप लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे व्यावहारिक और टिकाऊ समाधान भी प्रस्तुत करने चाहिए। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे समय में ऊर्जा मूल्य निर्धारण की नीति केवल राजनीतिक बहस का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक संतुलन का प्रश्न है। सरकार को राजस्व और जनहित के बीच संतुलन बनाना होगा, जबकि विपक्ष को तथ्य आधारित आलोचना करनी होगी। अंततः किसी भी आर्थिक नीति की सफलता इसी में है कि उसका लाभ आम नागरिक तक पहुंचे।

शरद पवार गुट की अहम बैठक

महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ी हलचल

अब सभी की नजर आने वाले दिनों पर टिकी है। यदि विपक्षी दल साझा रणनीति को अंतिम रूप देते हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। स्थानीय चुनावों के साथ-साथ भविष्य की राज्य स्तरीय राजनीति पर भी इस बैठक का असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

महाराष्ट्र की राजनीति में 15 जुलाई को उस समय हलचल और तेज हो गई, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की मुंबई में अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी प्रमुख शरद पवार, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा करना, आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की रणनीति तय करना और विपक्षी दलों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर चर्चा करना रहा। बैठक ऐसे समय हुई है, जब राज्य में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं और सभी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं।सूत्रों के मुताबिक, बैठक में संगठन को जिला और बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। पार्टी नेतृत्व ने नेताओं से कहा कि वे जनता के बीच जाकर महंगाई, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएं। इसके अलावा आगामी नगर निगम और जिला परिषद चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों और संगठनात्मक बदलावों पर भी चर्चा हुई। पार्टी का मानना है कि स्थानीय चुनाव भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनसीपी (शरदचंद्र पवार) जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करती रहेगी। नेताओं का कहना था कि विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है ताकि सरकार को प्रभावी ढंग से घेरा जा सके। हालांकि बैठक के दौरान किसी नए राजनीतिक गठबंधन या बड़े फैसले की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन नेताओं ने यह जरूर संकेत दिया कि आने वाले दिनों में विपक्षी एकजुटता को लेकर बातचीत और तेज होगी।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ वर्षों में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद विपक्ष अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में शरद पवार गुट की यह बैठक केवल संगठनात्मक समीक्षा तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे भविष्य की राजनीतिक रणनीति तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खासकर स्थानीय निकाय चुनावों से पहले विपक्ष अपनी ताकत बढ़ाने के लिए साझा रणनीति पर काम कर सकता है।उधर, सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने विपक्ष की बैठक को लेकर कहा कि जनता विकास के मुद्दों पर सरकार के साथ है और विपक्ष केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। सरकार का दावा है कि राज्य में बुनियादी ढांचे, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है।

शहीद दिवस रैली को हाईकोर्ट की मंजूरी, बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच सियासी घमासान तेज

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल की राजनीति में 15 जुलाई को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को 21 जुलाई को होने वाली वार्षिक 'शहीद दिवस रैली' आयोजित करने की अनुमति दे दी। हालांकि अदालत ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तें भी लगाईं और प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अदालत के इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है।टीएमसी के लिए शहीद दिवस रैली केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पार्टी की सबसे बड़ी वार्षिक शक्ति-प्रदर्शन सभा मानी जाती है। हर साल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करती हैं और राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट करती हैं। इस बार भी लाखों कार्यकर्ताओं के कोलकाता पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए टीएमसी नेताओं ने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत है। उनका कहना है कि

पार्टी हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम आयोजित करती रही है और इस बार भी अदालत के सभी निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि रैली के जरिए राज्य सरकार की उपलब्धियों, कल्याणकारी योजनाओं और आगामी राजनीतिक रणनीति को जनता के सामने रखा जाएगा।वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस रैली को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए करती है और प्रशासनिक मशीनरी पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। भाजपा ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक कार्यक्रमों का स्वागत है, लेकिन कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगले वर्ष होने वाले चुनावों से पहले यह रैली टीएमसी के लिए अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का बड़ा अवसर होगी। ममता बनर्जी के भाषण पर भी पूरे देश की नजर रहेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि वह विपक्षी एकजुटता, केंद्र-राज्य संबंधों और आगामी चुनावी रणनीति पर बड़ा संदेश दे सकती हैं।

सोनम वांगचुक के अनशन ने पकड़ा राजनीतिक रंग विपक्ष ने केंद्र सरकार से संवाद की मांग तेज की

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन 15 जुलाई को 18वें दिन में प्रवेश कर गया। लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के बीच यह आंदोलन अब केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा विषय बनता जा रहा है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी इस अनशन को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से तत्काल बातचीत शुरू करने और आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है।15 जुलाई को वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता और बढ़ गई। आंदोलन से जुड़े लोगों का दावा है कि उनका वजन लगातार कम हुआ है और कमजोरी बढ़ने के बावजूद उन्होंने अपना अनशन समाप्त करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे समूह ने 16 जुलाई को देशभर में प्रतीकात्मक सामूहिक उपवास का भी आह्वान किया है, ताकि छात्रों और अभिभावकों की आवाज को और मजबूती मिल सके।इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं ने वांगचुक के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से संवाद शुरू करने की मांग की है। कई सांसदों और सार्वजनिक हस्तियों ने भी जंतर-मंतर पहुंचकर या सोशल मीडिया के माध्यम से अपना समर्थन जताया। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों की बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई औपचारिक राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, हालांकि प्रशासन का कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उधर, दिल्ली हाईकोर्ट में भी वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर ध्यान देने की बात कही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत नहीं

होती, तो यह मुद्दा मानसून सत्र के दौरान संसद में भी जोर-शोर से उठ सकता है। फिलहाल पूरे देश की नजर इस बात पर है कि सरकार इस बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव से कैसे निपटती है और क्या किसी संवाद की शुरुआत होती है।

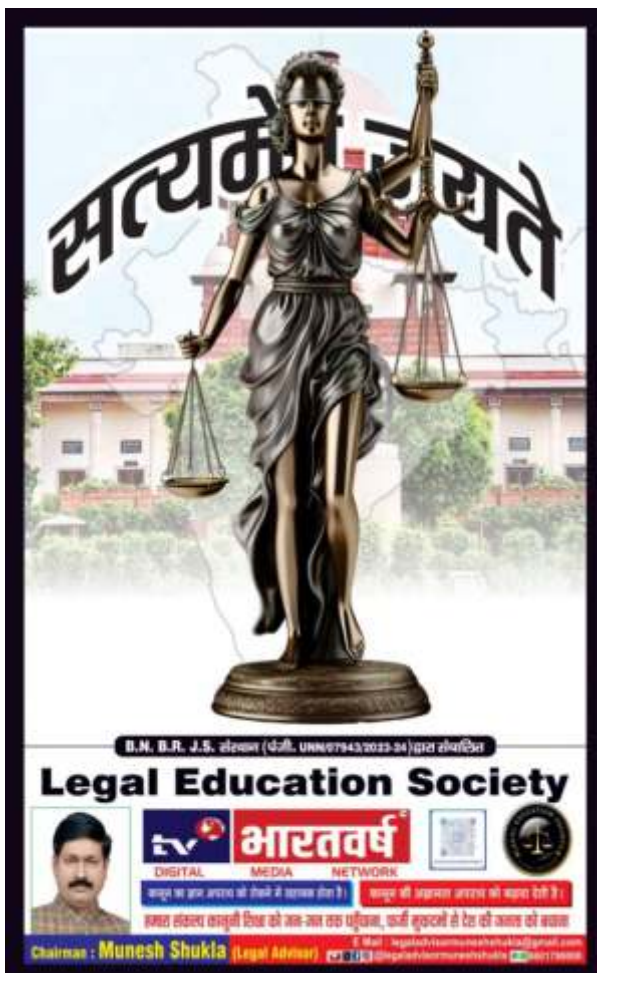

एमपीपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर भर्ती आवेदन शुरू, जानें पात्रता, फीस और चयन प्रक्रिया

शहरों-कस्बों के विकास और उन्हें डिजाइन करने का शौक है, तो आपकी प्रोफाइल से मिलती-जुलती सरकारी भर्ती निकली हुई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने असिस्टेंट टाउन प्लानर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य कैंडिडेट्स जो यह नौकरी पाना चाहते हैं, वो इस आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध एप्लिकेशन लिंक से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सहायक नगर नियोजक की यह भर्ती नगरीय विकास विभाग के लिए निकाली गई है। इस पद पर नियुक्त सरकारी अधिकारी शहरों के मास्टर प्लान और विकास योजनाओं पर काम करते हैं। उनपर बिल्डिंग और भूमि उपयोग से जुड़े प्रस्ताव, अवैध निर्माण, सड़क, पार्क, सार्वजनिक और बुनियादी स्वरूप की देखरेख की भी जिम्मेदारी होती है। जो अभ्यर्थी इसी फील्ड में सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह शानदार मौका हो सकता है। आवेदन की प्रक्रिया 31 जुलाई तक ऑनलाइन चलेगी। एमपी असिस्टेंट टाउन प्लानर भर्ती के लिए योग्यता

शैक्षिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निवेश में स्नातक की डिग्री (चार साल की) या नगर निवेश या शहरी निवेश/ नगरीय निवेश अथवा आवास निवेश या ग्रामीण निवेश/ अधोसंरचना निवेश/क्षेत्रीय निवेश या यातायात एंव परिवहन निवेश या भूदृष्य वास्तुकला अथवा नगर रुपांकन/पर्यावरण निवेश में पोस्ट ग्रेजुएशन (एम प्लान) अथवा एआईटीपी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ध्यान रखें कि यातायात एंव परिवहन में बी.ई या एम.ई की डिग्री स्वीकार नहीं होगी।

उम्र सीमा: आवेदक ने कम से कम 21 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो लेकिन 40 साल की आयु न हुई हो। ऊपरी उम्र में रिजर्व कैटेगिरी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट मिलेगी। उम्र की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। इस सरकारी भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन ओएमआर बेस्ड लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा। पेपर में निगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर पदों के तीन गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सेलेक्शन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों में प्राप्त स्कोर के आधार पर होगा। इंटरव्यू से पहले कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें योग्य पाए गए अभ्यर्थी ही भर्ती के अगले चरणों में आगे बढ़ेंगे। अगर अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होती है तो ऐसी स्थिति में इंटरव्यू के जरिए सेलेक्शन किया जा सकता है। एमपी की इस भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जनरल/अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को 540 रुपये आवेदन शुल्क भरना होगा। वहीं ओबीसी/एसटी/एससी कैंडिडेट्स को 210 रुपये फॉर्म फीस का भुगतान करना होगा।

डीयू में पहले से दो साल के 74 पोस्टग्रैजुएट कोर्सेज हैं, इनके लिए करीब 13500 सीटें

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक साल के 46 पोस्टग्रैजुएट कोर्सेज के लिए दाखिले होंगे। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हैं। पहली बार डीयू में एक साल के पीजी कोर्स शुरू हो रहे हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने डीयू से चार साल का अंडरग्रैजुएट कोर्स पूरा किया है। डीयू में पहले से दो साल के 74 पोस्टग्रैजुएट कोर्सेज हैं, इनके लिए करीब 13500 सीटें हैं। वहीं, एक साल के पीजी कोर्स 46 हैं, जिनकी सीटें 1100 से ज्यादा हैं यानी कुल मिलाकर इस साल 14600 सीटों पर दाखिले होंगे। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 जुलाई है। दो साल के पीजी के अलावा अब एक साल के 46 कोर्स शुरू होने के साथ-साथ डीयू के टीचर्स का वर्कलोड भी बढ़ेगा, डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कुछ दिक्कतें आएंगी। हालांकि, डीयू के वाइस चांसलर प्रो योगेश सिंह का कहना है कि रूटीन चैलेंज तो होंगे मगर मुझे नहीं लगता ज्यादा दिक्कतें आएंगी। इसके लिए टाइमटेबल पर विभागों ने काम शुरू हो कर दिया है। अगर दिक्कतें या शिकायतें आती हैं, तो हम इस पर तुरंत काम करेंगे। उनका कहना है कि यह एक साल के पीजी का पहला साल है, इसे अच्छी तरह से शुरू किया जाएगा। वैसे हमारी पास फैकल्टी की कमी नहीं है, परमानेंट अपॉइंटमेंट के बाद पर्याप्त टीचर्स आ चुके हैं। दूसरी ओर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी धीरे-धीरे पूरी हो रही है। डीयू कंप्यूटर सेंटर की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, फैकल्टी ऑफ टेक्नलॉजी की बिल्डिंग दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। डीयू में NEP (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) के तहत 2022 में चार साल का यूजी शुरू किया, जिसका पहला बैच इस साल पासआउट कर रहा है। करीब 20 हजार स्टूडेंट्स ने मेजर के साथ चार साल का यूजी पूरा किया है।

ओस्लो में नॉर्वे टीम का ऐतिहासिक स्वागत 1 लाख से ज्यादा Fans ने मनाया जश्न

इंग्लैंड में भारत की शानदार शुरुआत पहले वनडे में 6 विकेट से जीत

भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड दौरे की वनडे सीरीज की शुरुआत शानदार अंदाज में करते हुए पहले मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। एजबेस्टन, बर्मिंघम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों विभागों में संतुलित प्रदर्शन किया। टी20 सीरीज में मिली निराशा के बाद यह जीत टीम इंडिया के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली साबित हुई। इस जीत के साथ कप्तान शुभमन गिल ने वनडे कप्तान के रूप में भी अपनी रणनीतिक क्षमता का परिचय दिया।मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तेज शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर मेजबान टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्यक्रम को झकझोर दिया। तेज गेंदबाजों ने भी नई गेंद और डेथ ओवरों में अनुशासित गेंदबाजी की, जिसके कारण इंग्लैंड चुनौतीपूर्ण लेकिन बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा नहीं कर सका। भारतीय गेंदबाजों की लाइन-लेंथ और फील्डिंग इस मुकाबले की सबसे बड़ी ताकत रही।लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी आत्मविश्वास से भरी रही। कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभालते हुए 80 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने शुरुआत में विकेट बचाने पर ध्यान दिया और बाद में आक्रामक शॉट लगाकर रनगति को तेज किया। दूसरे छोर से अक्षर पटेल ने उपयोगी पारी खेलते हुए कप्तान का अच्छा साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में ला दिया। अंत में वॉशिंगटन सुंदर और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने बिना किसी दबाव के लक्ष्य हासिल कर भारत को छह विकेट से यादगार जीत दिला दी।मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि टीम ने टी20 सीरीज की गलतियों से सीख ली है और खिलाड़ियों ने परिस्थितियों के अनुसार क्रिकेट खेला। उन्होंने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा कि शुरुआती विकेटों ने मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। वहीं अक्षर पटेल को उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए विशेष सराहना मिली। इंग्लैंड के कप्तान ने माना कि उनकी टीम अहम मौकों पर साझेदारियां नहीं बना सकी और यही हार की सबसे बड़ी वजह रही।

अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर स्पेन से खिताबी मुकाबला पक्का किया

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल फुटबॉल प्रशंसकों के लिए यादगार बन गया। 15 जुलाई को अटलांटा में खेले गए रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली। मुकाबले में इंग्लैंड ने दूसरे हाफ में बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन आखिरी मिनटों में अर्जेंटीना ने शानदार वापसी करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अब विश्व कप का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा।मैच का पहला हाफ गोलरहित रहा, लेकिन दोनों टीमों ने लगातार आक्रामक फुटबॉल खेली। दूसरे हाफ के 55वें मिनट में इंग्लैंड के एंथनी गॉर्डन ने शानदार गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड फाइनल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अर्जेंटीना ने दबाव बनाए रखा। 85वें मिनट में मिडफील्डर एंज़ो फर्नांडीज़ ने बराबरी का गोल दागकर मुकाबले को फिर से रोमांचक बना दिया। इसके बाद इंजरी टाइम में कप्तान लियोनेल मेसी ने बेहतरीन असिस्ट दिया, जिस पर लाउतारो मार्टिनेज़ ने विजयी गोल कर अर्जेंटीना को 2-1 की ऐतिहासिक जीत दिला दी।39 वर्षीय लियोनेल मेसी एक बार फिर टीम के सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए। पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है और वह गोल्डन बूट की दौड़ में भी सबसे आगे चल रहे हैं। मैच के बाद मेसी ने कहा कि उनकी टीम ने अंत तक हार नहीं मानी और यही जज़्बा उन्हें फाइनल तक लेकर आया। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने हार पर निराशा जताई, लेकिन टीम के संघर्ष की सराहना भी की गई। अब 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच विश्व कप का महामुकाबला खेला जाएगा। स्पेन ने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि यह फाइनल दो सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच होगा, जहां एक ओर मेसी के अनुभव की परीक्षा होगी तो दूसरी ओर स्पेन की युवा और तेज़-तर्रार टीम अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगी। दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रशंसकों की निगाहें अब इस ऐतिहासिक फाइनल पर टिकी हुई हैं।

वनडे वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट का किया ऐलान, 14 टीमों के बीच होगी खिताब की जंग

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 15 जुलाई को वर्ष 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले पुरुष वनडे विश्व कप के लिए नए टूर्नामेंट फॉर्मेट की घोषणा कर दी। इस बदलाव के साथ विश्व कप में एक बार फिर 14 टीमें हिस्सा लेंगी और प्रतियोगिता पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी और लंबी होगी।।ICC का कहना है कि नए प्रारूप का उद्देश्य अधिक टीमों को मौका देना, रोमांचक मुकाबले बढ़ाना और नॉकआउट चरण तक पहुंचने की प्रतिस्पर्धा को और कड़ा बनाना है।नए प्रारूप के अनुसार, मुख्य प्रतियोगिता में पहुंचने से पहले एक प्रारंभिक चरण खेला जाएगा। इसके बाद 12 टीमें दो समूहों में बांटी जाएंगी, जहां प्रत्येक टीम अपने समूह की अन्य टीमों से मुकाबला करेगी। ग्रुप चरण के बाद शीर्ष टीमें 'सुपर-7' चरण में पहुंचेंगी, जहां अंक और प्रदर्शन के आधार पर सेमीफाइनल के लिए चार टीमों का चयन होगा। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।।ICC का मानना है कि इस व्यवस्था से पूरे टूर्नामेंट में हर मैच का महत्व बना रहेगा और टीमों को अंतिम समय तक संघर्ष करना होगा।इस नए फॉर्मेट के सामने आते ही क्रिकेट जगत में चर्चा तेज हो गई है। कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसे अधिक प्रतिस्पर्धी बताते हुए स्वागत किया है, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नया प्रारूप थोड़ा जटिल हो सकता है और दर्शकों को इसे समझने में समय लगेगा। वहीं क्रिकेट प्रशंसकों के बीच सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर है कि नए ढांचे में भारत और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों के बीच एक से अधिक मुकाबले देखने की संभावना बढ़ सकती है, यदि दोनों टीमें आगे के चरणों में पहुंचती हैं।ICC ने स्पष्ट किया

है कि यह बदलाव केवल मैचों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि प्रतियोगिता को अधिक संतुलित और रोमांचक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। बोर्ड का मानना है कि इससे उभरती क्रिकेट टीमों को भी विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर अवसर मिलेगा। अब क्रिकेट प्रेमियों की नजर 2027 विश्व कप की तैयारियों पर है, क्योंकि नए फॉर्मेट के साथ यह टूर्नामेंट रणनीति, फिटनेस और निरंतर प्रदर्शन की सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।

व्लॉगर ने दिखाई झलक

गेट्स ने 370 करोड़ में खरीदा बीच हाउस

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कैलिफोर्निया के डेल मार स्थित उनके समुद्र किनारे बने लग्जरी घर को दिखाया जा रहा है. वीडियो में दावा किया गया है कि बिल गेट्स ने करोड़ों रुपये में खरीदे इस घर को बाद में पूरी तरह तुड़वाकर दोबारा बनवाया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिल गेट्स और उनकी तत्कालीन पत्नी मेलिंडा गेट्स ने मार्च 2020 में कैलिफोर्निया के डेल मार इलाके में समुद्र के किनारे स्थित यह प्रॉपर्टी 4.3 करोड़ डॉलर (करीब 370 करोड़ रुपये) में खरीदी थी. उस समय यह सैन डिएगो काउंटी की सबसे महंगी रिहायशी खरीद में शामिल थी. यह घर पहले अरबपति टी. बून पिकेंस की पूर्व पत्नी मेडेलिन पिकेंस के पास था. करीब 5,800 वर्ग फुट में फैले इस बीच हाउस में 6 बेडरूम, 4 बाथरूम, 120 फीट का डायरेक्ट ओशन फ्रंटेज और अलग से 2 बेडरूम का गेस्ट हाउस है.

मशहूर आर्किटेक्ट केन रोंकेटी द्वारा डिजाइन किए गए इस घर में समुद्र की ओर खुलने वाली बड़ी ग्लास वॉल्स, ग्लास-टाइल स्विमिंग पूल, 10 लोगों की क्षमता वाला ओशनफ्रंट जकूजी, हेल्थ स्पा, होम थिएटर और कई प्रीमियम सुविधाएं मौजूद थीं. सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हुई कि अच्छी हालत में होने के बावजूद इस घर को पूरी तरह हटाकर दोबारा बनाया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिल गेट्स ने सिर्फ मरम्मत नहीं करवाई, बल्कि पूरे घर का रीबिल्ड कराया.

येलोस्टोन पार्क में खौफनाक मंजर

900 किलो के बाइसन ने पर्यटक को 8 फीट हवा में उछाला

अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में छुट्टियां मनाने आए एक पर्यटक के लिए सैर कुछ ही सेकंड में डरावने हादसे में बदल गई. करीब 900 किलो वजनी एक बाइसन ने अचानक हमला कर दिया और शख्स को अपने सींग से उछालकर करीब 8 फीट हवा में फेंक दिया. पूरी घटना वहां मौजूद एक वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर के कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अगर आप बाइसन के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो बता दें कि यह दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर स्थलीय स्तनधारियों में से एक है. अमेरिका और कनाडा में बड़ी संख्या में पाए जाने

वाले बाइसन का वजन 900 किलोग्राम या उससे भी ज्यादा हो सकता है. मेटिंग (रटिंग) सीजन के दौरान नर बाइसन का स्वभाव काफी आक्रामक हो जाता है. यही वजह है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क प्रशासन पर्यटकों को इनसे कम से कम 25 गज (करीब 23 मीटर) की दूरी बनाए रखने की सलाह देता है.

मर्दों के सैलून पहुंची रूसी महिला

रूसी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर केल्यूबा लिउबोव का दिल्ली के एक मेंस सैलून में फेस मसाज कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मात्र 1 डॉलर (₹85) में लिए गए इस देसी अनुभव और भारतीय मेहमाननवाजी की उन्होंने जमकर तारीफ की है.

भारत में नाई की दुकान सिर्फ बाल कटवाने की जगह नहीं होती. यहां कुर्सी पर बैठने के बाद कई बार ग्राहक हेयरकट से ज्यादा फेस मसाज और सिर की मालिश का इंतजार करता है.

कोई एसी सैलून में इस सुख का आनंद लेता है, तो कोई गली के कोने वाली दुकान या पेड़ की छांव में बैठे बार्बर के हाथों का कमाल देखता है. अब भारतीय सैलून का यही देसी अंदाज विदेशियों को भी लुभाने लगा है. रूस की ट्रैवल इन्फ्लुएंसर केल्यूबा लिउबोव ने भी सोचा कि जब भारत आए हैं तो देसी सैलून का अनुभव क्यों न लिया जाए. बस फिर क्या था. वह दिल्ली के एक पुरुषों के सैलून में पहुंच गईं और करीब 1 डॉलर (करीब 85 रुपये) में फेस मसाज करवा डाली. अब उनका यही अनुभव सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में बार्बर पहले बड़े आराम से उनके बाल क्लिप से पीछे बांधता है, फिर क्रीम लगाकर चेहरे की मसाज शुरू कर देता है. इस बीच दुकान में मौजूद लोग भी समझ जाते हैं कि आज का दिन थोड़ा अलग है. कोई आईने के सामने उनके साथ सेल्फी लेने लगता है, तो बाकी ग्राहक भी उत्सुकता से पूरा नजारा देखते रहते हैं.

देसी बार्बर के हाथों का जादू आया पसंद

वीडियो शेयर करते हुए लिउबोव ने लिखा कि नई दिल्ली में फेस मसाज करवाना अपने आप में एक अलग अनुभव है. उनके चेहरे की मुस्कान भी यही बता रही थी कि देसी बार्बर के हाथों का जादू उन्हें पसंद आया. केल्यूबा इन दिनों भारत घूम रही हैं. उनके इंस्टाग्राम पर ताजमहल, पुरानी दिल्ली की गलियां, गुरुद्वारे, मंदिर और कई मशहूर पर्यटन स्थलों की झलक देखने को मिलती है. उन्होंने अपनी पोस्ट में भारत को सुरक्षित जगह भी बताया है और यहां के लोगों की मेहमाननवाजी की तारीफ की है.

श्रीलंका में भारतीय महिला को लगा कल्चर शॉक

क्या पड़ोसी देश भारत से भी ज्यादा साफ-सुथरा और अनुशासित हो सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के बाद यही सवाल चर्चा में है. भारतीय महिला रूथ डिसूजा प्रभु ने श्रीलंका की यात्रा के अपने अनुभव साझा किए हैं. उन्होंने कहा कि वहां की कुछ बातें देखकर उन्हें 'कल्चर शॉक' लगा और उनका मानना है कि भारत भी अपने पड़ोसी देश से कई बातें सीख सकता है.

अगले साल आएगी सलमान की फिल्म

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अगली फिल्म मातृभूमि की राह ताक रहे फैंस का इंतजार और लंबा हो सकता है.

अगर सब ठीक रहता तो इस साल सलमान फैंस को ईद पर अपने हीरो की नई फिल्म देखने को मिल जाती, लेकिन लगातार टलती जा रही इस फिल्म की राह अभी भी आसान नहीं नजर आ रही.

मातृभूमि पहले इस साल अप्रैल के लिए शेड्यूल की गई थी, लेकिन भारत-चीन सीमा विवाद पर बेस्ड इस फिल्म पर कुछ आपत्तियों के बाद पहले कंटेंट में कुछ बदलावों के लिए फिल्म को टाला गया. फिर खबर आई कि मातृभूमि इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आ सकती है, लेकिन अब सामने आ रहा है कि सलमान की फिल्म अगले साल तक भी जा सकती है. बॉलीवुड हंगामा से जुड़े एक ट्रेड सूत्र ने बताया है कि मातृभूमि के मेकर्स इस साल ही फिल्म रिलीज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हालांकि अब ये भी एक संभावना है कि फिल्म 2027 तक टल सकती है. सूत्र ने बताया, 'मामला अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं है.

अगर जल्द सुलझ भी जाता है, तो भी अच्छी रिलीज डेट मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर बड़े स्लॉट पहले ही बुक हो चुके हैं.

इंटरनेट पर दिव्या का 'बिकिनी ब्लास्ट'

बॉलीवुड एक्ट्रेस, मॉडल, फिल्ममेकर और टी-सीरीज (T-Series) के मालिक और चेयरमैन भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. दिव्या खोसला की नई बोल्ड तस्वीरों ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी हैं.दिव्या खोसला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्पोर्ट्स बिकिनी में अपनी किलर तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस बिकिनी में कहर ढाती नजर आईं.

69000 शिक्षक भर्ती : आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का एससीईआरटी कार्यालय पर प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट में याची लाभ देने का प्रस्ताव

लखनऊ। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण से जुड़े विवाद को लेकर आरक्षण पीड़ित याची अभ्यर्थियों ने मंगलवार को लखनऊ स्थित एससीईआरटी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। विभिन्न जिलों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से मांग की कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई के दौरान वर्ष 2020 से याचिकाकर्ता बने अभ्यर्थियों को %याची लाभ% देने का प्रस्ताव रखा जाए, ताकि लंबे समय से लंबित विवाद का समाधान हो सके। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना था कि वे पिछले छह वर्षों से न्यायालय में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला भी उनके पक्ष में आया है। इसके बावजूद सरकार उनकी मांगों पर निर्णय नहीं ले रही है। उनका कहना है कि याचिकाकर्ताओं को लाभ देने से किसी भी वर्ग का अहित नहीं होगा और विवाद का समाधान संभव हो सकेगा। कुछ अभ्यर्थियों ने भर्ती की सूची का पुनरीक्षण (रिविजिट) करने की भी मांग उठाई। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने कहा कि 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मामला वर्ष 2020 में हाईकोर्ट पहुंचा था। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की डबल बेंच ने भर्ती सूची को निरस्त किया था। हालांकि, उनका संगठन छह वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को हटाने के पक्ष में नहीं है, बल्कि केवल उन अभ्यर्थियों को याची लाभ दिए जाने की मांग कर रहा है जो वर्ष 2020 से लगातार न्यायालय में पक्षकार बने हुए हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ के समक्ष होने वाली सुनवाई में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को लाभ देने का प्रस्ताव रखा जाए, जिससे विवाद का स्थायी समाधान निकल सके। धरना-प्रदर्शन में सुशील कश्यप, धनंजय गुप्ता, मोहित, विक्रम, सुशील, संदीप, विशाल समेत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे।

सीडीआरआई एलुमनाई ने छात्राओं को विज्ञान के लिए किया प्रेरित

लखनऊ। सीएसआईआर-केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान एलुमनाई एसोसिएशन ने मंगलवार को आर्य कन्या पाठशाला, निशातगंज में विज्ञान जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान छात्राओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना था। इस अवसर पर नई दवा की खोज एक संक्षिप्त परिचय विषय पर व्याख्यान हुआ। सीडीआरआई के वरिष्ठ पूर्व छात्र डॉ. विष्णु लाल शर्मा एवं प्रो. अर्चना तलवार ने नई दवा के विकास की पूरी प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने बताया कि किसी दवा के विकास में रोग की पहचान, उपचार लक्ष्य का चयन, संभावित औषधीय अणुओं की खोज, प्रीक्लिनिकल व क्लिनिकल परीक्षण तथा नियामकीय स्वीकृतियों जैसी कई वैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वक्ताओं ने नवाचार, अनुसंधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जैव-चिकित्सा अनुसंधान में उपलब्ध करियर अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से वैज्ञानिक अनुसंधान को करियर के रूप में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र में छात्राओं ने दवा विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान और विज्ञान में करियर से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने विस्तार से उत्तर दिया।

हरित ऊर्जा पर केंद्रित कार्यशाला पर चर्चा

लखनऊ। रीजनल साइंस सिटी में 13 जुलाई को 32वीं नेशनल चिल्ड्रन्स साइंस कांग्रेस (उत्तर प्रदेश-पश्चिम) के तहत कार्यशाला आयोजित हुई। एलपीसीपीएस के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एवं वरिष्ठ प्लेसमेंट प्रमुख प्रो. (डॉ.) ओम प्रकाश ने रिसोर्स पर्सन और वक्ता के रूप में विज्ञान के विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रयोगों की उपयोगिता और महत्व की जानकारी दी। उन्होंने हाइड्रोजन आधारित हरित ऊर्जा पर शोध और प्रयोग को ऊर्जा संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही विद्यार्थियों को प्रयोग तैयार करने और शोध प्रस्तुत करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग की जानकारी दी। प्रो. ओम प्रकाश ने कार्यशाला के आयोजन के लिए एनसीएससी-यूपी वेस्ट के स्टेट प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ. वीपी सिंह को बधाई दी।

अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड समेत 3 और गिरफ्तार

लखनऊ। विदेशी नागरिकों, विशेषकर अमेरिका के लोगों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर मामले में लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी मास्टरमाइंड विनीत वशिष्ठ समेत तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है। गौरतलब है कि 1 जुलाई को लखनऊ पुलिस की साइबर क्राइम सेल और साइबर क्राइम थाने की संयुक्त टीम ने राजधानी में संचालित एक अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया था। कार्रवाई के दौरान 119 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था तथा बड़ी संख्या में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सर्वर सहित साइबर अपराध में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए थे। इस मामले में थाना साइबर क्राइम में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जांच में सामने आया कि अमेरिका में मौजूद साइबर ठग पहले अमेरिकी टोल-फ्री नंबर खरीदते थे। इसके बाद इन नंबरों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भारत में बैठे गिरोह के सदस्यों तक पहुंचाया जाता था। चूंकि इन नंबरों पर कॉल निशुल्क होती थी, इसलिए अमेरिकी नागरिकों को झांसे में लेने के लिए उनके मोबाइल पर बड़ी संख्या में संदेश भेजे जाते थे, ताकि वे शिकायत दर्ज कराने या सहायता लेने के बहाने उन्हीं टोल-फ्री नंबरों पर कॉल करें। इसके बाद कॉल सेंटर के कर्मचारी खुद को अधिकृत प्रतिनिधि बताकर लोगों से बैंकिंग और अन्य गोपनीय जानकारियां हासिल कर साइबर ठगी को अंजाम देते थे।विवेचना के दौरान लखनऊ पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए कई अमेरिकी टोल-फ्री नंबरों की पहचान की है। पुलिस इन नंबरों का विवरण उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के माध्यम से अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करेगी, ताकि वहां मौजूद साइबर अपराधियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सके।पुलिस ने बताया कि अमेरिका में सोमोस संस्था टोल-फ्री नंबरों के पंजीकरण और प्रबंधन का कार्य करती है, जबकि ट्रेसबैक संस्था संदिग्ध और धोखाधड़ी वाले कॉल के स्रोत का पता लगाने में सहयोग करती है। भारतीय एजेंसियों की ओर से साझा की गई जानकारी के आधार पर अमेरिकी प्राधिकरण इन संस्थाओं की मदद से आगे की जांच करेंगे। जांच के दौरान जिस परिसर से कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था, उसका किरायानामा भी पुलिस के हाथ लगा है। जांच में पता चला कि यह किरायानामा सोलारिस सॉल्यूशन के नाम पर नहीं, बल्कि जाइकॉम टेक्नोलॉजीज के नाम पर किया गया था। जांच में इस कंपनी का कानूनी स्वामित्व गिरफ्तार आरोपी नायकर जयराज से जुड़ा पाया गया है।पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के वित्तीय लेन-देन की भी गहन जांच कर रही है। हवाला के माध्यम से धन के आदान-प्रदान और साइबर ठगी से अर्जित रकम के प्रवाह (मनी ट्रेल) की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे भी गिरफ्तारियां और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

■ ऐसे बनाते थे अमेरिकी नागरिकों को शिकार

बरगद बचाओ महाअभियान से गूंजा विद्यालय बच्चों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

वृक्षजल कथा के माध्यम से वृक्ष, जल और जीवन का बताया महत्व, जागरूकता रैली निकाली गई

उन्नाव। विकासखंड औरास के उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर गढ़ौवा में पर्यावरण उत्सव के तहत आयोजित वृक्षजल कथा एवं बरगद बचाओ महाअभियान ने बच्चों और ग्रामीणों को प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। पुलिस कंट्रोल रूम प्रभारी एवं वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनूप मिश्र अपूर्व तथा शिक्षक प्रदीप कुमार वर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के बजाय मां सरस्वती और बरगद के पौधे का पूजन एवं जल अर्पित कर किया गया। इसके बाद वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनूप मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर बरगद बचाओ महाअभियान की जनजागरण रैली को रवाना किया। बरगद हम बचाएंगे, बरगद हम लगाएंगे जैसे नारों के साथ निकली रैली ने विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

रैली के बाद आयोजित वृक्षजल कथा में वृक्ष, जल और जीवन के परस्पर संबंध को सरल और प्रेरक ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद बच्चों और शिक्षकों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण पर्यावरण विषय पर आयोजित पॉडकास्ट संवाद रहा। इसमें छात्राओं समरीन, अंकिता, दीपाली और शगुन ने जल संकट, वृक्षों की उपयोगिता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सवाल पूछे। वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनूप मिश्र ने उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए बच्चों को प्रकृति का सच्चा प्रहरी बनने का संदेश दिया।

आयोजन के दौरान मैं बरगद का मित्र सेल्फ स्टैंड और बरगद प्रह हस्ताक्षर अभियान आकर्षण का केंद्र र विद्यार्थियों, शिक्षकों अ अतिथियों ने हस्ताक्ष कर बरगद संरक्षण अ अधिक से अधिक पौ लगाने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर पर्यावर संरक्षण में उत्कृ योगदान देने वा विद्यार्थियों को सम्मानि किया गया। विद्याल परिसर को हराभरा बनाने में योगदान के लि शिक्षक इंद्रपाल को सम्मानित किया गया, जबकि शिक्षक प्रदीप कुमार वर्मा को बरगद बचाओ महाअभियान को अधिक से अधिक विद्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

अपने संबोधन में वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनूप मि ने विद्यालय की स्वच्छता, हरियाली और नवाचा की सराहना करते हुए इसे जनपद का प्रेरणादा मॉडल विद्यालय बताया। उन्होंने कहा कि य प्रत्येक विद्यालय बच्चों को प्रकृति से जोड़ने ऐसा प्रयास करे तो पर्यावरण संरक्षण ए जनआंदोलन का रूप ले सकता है। कार्यक्रम संचालन शिक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने किया।

धान रोपाई के बीच सूखी पड़ी न्योतनी रजबहा, पानी को तरसे किसान

एक सप्ताह से नहर बंद, इंजन से सिंचाई करने को मजबूर किसान, पुल निर्माण और सफाई कार्य बना वजह

अखिल द्विवेदी (ब्यूरो)

हंसनगज उन्नाव। प्रदेश सरकार किसानों को हर संभव सुविधा देने का दावा कर रही है, लेकिन हसनगंज क्षेत्र में धान की रोपाई के सबसे महत्वपूर्ण समय पर किसान सिंचाई के पानी के लिए परेशान हैं। आशीवन नहर से निकली न्योतनी रजबहा पिछले एक सप्ताह से सूखी पड़ी है। बारिश न होने और नहर में पानी बंद रहने से किसानों को महंगे डीजल इंजन के सहारे खेतों की सिंचाई करनी पड़ रही है, जिससे खेती की लागत लगातार बढ़ रही है।

धान रोपाई के चरम दौर में नहर सूख जाने से किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। खेतों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने से रोपाई का कार्य प्रभावित हो रहा है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द पानी नहीं छोड़ा गया तो फसल उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

ग्रामीणों ने बताया कि पिछली गेहूं की फसल के समय भी नहर की सफाई के कारण करीब एक महीने तक पानी बंद रहा था, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। अब धान की रोपाई के दौरान फिर वही स्थिति बनने से किसानों में विभाग के प्रति नाराजगी है। उनका कहना है कि हर बार कृषि सीजन में ही नहर बंद कर दी जाती है, जिससे उनकी मेहनत और पूंजी दोनों प्रभावित होती हैं।

क्षेत्र के किसान रविंद्र, रमेश, मुनेश, राजन, सुरेश, बलवंत, राजू और उमेश समेत दर्जनों किसानों ने बताया कि न तो बारिश हो रही है और न ही नहर में पानी आ रहा है। ऐसे में मजबूरी में डीजल इंजन से सिंचाई करनी पड़ रही है, जिससे प्रति बीघा सिंचाई का खर्च कई गुना बढ़ गया है।

किसानों का कहना है कि यदि मकूर में पुल निर्माण कराया जाना जरूरी था तो इसका समय धान रोपाई के बाद तय किया जाना चाहिए था। उनका आरोप है कि सबसे व्यस्त कृषि सीजन में नहर का पानी रोकना किसानों के हितों की अनदेखी है।

एक सप्ताह और करना होगा इंतजार

नहर विभाग के कर्मचारी कमलेश कुमार ने बताया कि नहर की सफाई और मकूर में पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है और नहर में पानी आने में अभी लगभग एक सप्ताह का समय लग सकता है। वहीं, सिंचाई विभाग की एसडीओ गीता कुमारी ने कहा कि पुल निर्माण का कार्य पूरा होते ही नहर में पानी छोड़ दिया जाएगा।

इनसेट- किसानों की प्रमुख समस्याएं

एक सप्ताह से सूखी पड़ी है न्योतनी रजबहा।

धान रोपाई के बीच सिंचाई का संकट गहराया।

डीजल इंजन से सिंचाई करने को मजबूर किसान।

पुल निर्माण और नहर सफाई के चलते रोका गया पानी।

विभाग ने पानी छोड़ने में अभी एक सप्ताह और लगने की बात कही।

बड़ा सवाल

क्या सिंचाई विभाग कृषि सीजन को ध्यान में रखकर कार्ययोजना नहीं बना सकता, ताकि निर्माण कार्य भी हो और किसानों की फसल भी प्रभावित न हो?

पेड़ से गिरा युवक, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर

स्वतंत्र भारत (ब्यूरो) नवाबगंज उन्नाव। सोहरामऊ थाना क्षेत्र के सराय जोगा गांव में मंगलवार सुबह महुआ तोड़ते समय एक युवक पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुरवा थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गांव निवासी अनिरुद्ध (23) पुत्र भोला प्रसाद इन दिनों सराय जोगा गांव में रहकर एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। मंगलवार सुबह वह गांव के बाहर महुआ तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह अचानक नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद साथियों ने तत्काल एंबुलेंस बुलाकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नवाबगंज पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल के दोस्त सुरेंद्र ने बताया कि अनिरुद्ध सराय जोगा गांव में रहकर एक कंपनी में काम करता है। हादसे के बाद उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है।

भगवान बख्श सिंह इंटर कॉलेज का पुरातन छात्र मिलन समारोह

स्वतंत्र भारत (ब्यूरो) उन्नाव। भगवान बख्श सिंह इंटर कॉलेज, बाजितपुर के पूर्व प्रधानाचार्य स्व. दुर्गा बख्श सिंह की जयंती के अवसर पर एक अगस्त को विद्यालय में पुरातन छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में वर्षों बाद पूर्व छात्र एक-दूसरे से मिलेंगे और अपने शिक्षकों के साथ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक एवं भाजपा नेता अजय मिश्र एडवोकेट ने बताया कि उन्होंने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा इसी विद्यालय से प्राप्त की है। पढ़ाई पूरी होने के बाद तीन-चार दशक बीत जाने के कारण अधिकांश सहपाठियों और शिक्षकों से मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसे में पूर्व प्रधानाचार्य स्व. दुर्गा बख्श सिंह की जयंती का अवसर सभी पूर्व छात्रों को एक मंच पर लाने के लिए उपयुक्त माना गया है। उन्होंने बताया कि समारोह में विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों के साथ उस समय के जीवित शिक्षकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। उनके सम्मान के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा और विद्यालय से जुड़ी पुरानी स्मृतियों को साझा किया जाएगा। अजय मिश्र ने अधिक से अधिक पूर्व छात्रों से कार्यक्रम में शामिल होकर अपने पुराने साथियों और गुरुओं से मिलने की अपील की है। उनका कहना है कि यह आयोजन केवल एक मिलन समारोह नहीं, बल्कि गुरु-शिष्य परंपरा और विद्यालय की गौरवशाली विरासत को सम्मान देने का अवसर होगा।

रफीगढ़ी ने जीता जेठ कबीर बाबा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब

फाइनल में मलकादिम सराय को 15 रन से हराया, प्रमोद बने मैन ऑफ द मैच

उन्नाव। विकासखंड क्षेत्र के रफीगढ़ी गांव में आयोजित जेठ कबीर बाबा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सोमवार रात रफीगढ़ी और मलकादिम सराय की टीमों के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में रफीगढ़ी ने 15 रन से जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रफीगढ़ी की टीम ने निर्धारित चार ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 65 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मलकादिम सराय की टीम चार ओवर में चार विकेट खोकर 51 रन ही बना सकी और मुकाबला 15 रन से गंवा बैठी।

रफीगढ़ी के खिलाड़ी प्रमोद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक ही ओवर में लगातार तीन विकेट झटके। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। विजेता टीम की कप्तानी योगेंद्र सिंह ने, जबकि उपविजेता मलकादिम सराय टीम का नेतृत्व मयंक सिंह ने किया।समाजसेवी प्रियांशु पंडित ने विजेता टीम रफीगढ़ी को 11 हजार रुपये नकद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं उपविजेता मलकादिम सराय की टीम को पांच हजार रुपये नकद और ट्रॉफी प्रदान की गई।

टूर्नामेंट का आयोजन अनुज शर्मा, सौरभ, पुष्पेंद्र, शालू और योगेंद्र समेत अन्य सहयोगियों के संयुक्त प्रयास से किया गया। आयोजकों ने कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास का सशक्त माध्यम है। ऐसे आयोजन न केवल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं, बल्कि आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता को भी मजबूत करते हैं। उन्होंने प्रत्येक गांव में इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर बल दिया, ताकि युवा मोबाइल की दुनिया से निकलकर खेलों से जुड़ें और अपनी प्रतिभा को निखार सकें।

एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के नाम में उन्नाव जोड़ने की उठी मांग

-कांग्रेस नेता, दैनिक यात्री संघ और पूर्व सैनिक बोले- 80 प्रतिशत भूमि उन्नाव की, महापुरुष के नाम पर हो नामकरण

----शिवम् बाजपेई----

उन्नाव। कानपुर-लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद इसके नामकरण को लेकर जनपद में चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष दिनेश शुक्ला, जिला दैनिक यात्री संघ और पूर्व सैनिक राजेश ने एक्सप्रेसवे के नाम में उन्नाव को शामिल करने अथवा इसका नाम जिले के किसी महापुरुष के नाम पर रखने की मांग की है। उनका कहना है कि परियोजना के लिए सबसे अधिक भूमि उन्नाव जनपद की अधिग्रहित की गई है, इसलिए नामकरण में भी जिले की पहचान को उचित स्थान मिलना चाहिए।

कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष दिनेश शुक्ला ने कहा कि किसी भी विकास परियोजना के पीछे उन किसानों और परिवारों का योगदान होता है, जिनकी जमीन उसके निर्माण में लगती है। उनका दावा है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 80 प्रतिशत भूमि उन्नाव जनपद की उपयोग में लाई गई है, जबकि इसका प्रमुख इंटरचेंज और चढ़ने-उतरने का मार्ग भी उन्नाव में ही स्थित है। इसके बावजूद परियोजना का नाम केवल कानपुर-लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे रखा जाना जनपद के योगदान के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने कहा कि उन्नाव के हजारों किसानों ने अपनी उपजाऊ कृषि भूमि देकर प्रदेश के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। ऐसे में एक्सप्रेसवे का नाम उन्नाव-लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे रखा जाए या फिर इसका नाम जिले के किसी स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार अथवा अन्य महापुरुष के नाम पर किया जाए। इसी मांग का समर्थन करते हुए जिला दैनिक यात्री संघ के अध्यक्ष मुर्तजा हैदर रिजवी ने भी केंद्र सरकार से नामकरण पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि परियोजना का अधिकांश हिस्सा उन्नाव की सीमा से होकर गुजरता है, जबकि कानपुर जनपद की भूमि का उपयोग इसमें नहीं हुआ। ऐसे में उन्नाव की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को सम्मान देते हुए एक्सप्रेसवे के नाम में उन्नाव को शामिल किया जाना चाहिए।

वहीं पूर्व सैनिक राजेश ने कहा कि विकास परियोजनाएं स्वागत योग्य हैं, लेकिन उनके पीछे किसानों के त्याग और बलिदान को भी याद रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्नाव की बड़ी मात्रा में उपजाऊ कृषि भूमि एक्सप्रेसवे निर्माण में लगी है। जिन किसानों ने अपनी पुश्तैनी जमीन देकर प्रदेश के विकास में योगदान दिया, उनके सम्मान के प्रतीक के रूप में एक्सप्रेसवे का नाम उन्नाव के किसी महान व्यक्तित्व के नाम पर रखा जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि उन्नाव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, साहित्यकारों और समाजसेवियों की धरती रही है। इसलिए नामकरण में जिले की गौरवशाली विरासत का सम्मान होना चाहिए।

चार्जिंग के दौरान स्कूटर की बैटरी में लगी आग, दो की मौत 50 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया

गौतम बुद्ध नगर पुलिस के जॉइंट कमिश्नर राजीव नारायण ने बताया कि इमारत में पार्किंग ग्राउंड फ्लोर पर थी, बेसमेंट में नहीं। इसी कारण पार्किंग में लगी आग से निकला धुआं तेजी से सीढ़ियों और अन्य रास्तों से ऊपरी मंजिलों तक फैल गया। धुएं की वजह से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

नोएडा के मामूरा गांव में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी चार्जिंग के दौरान लगी आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि फायर विभाग की त्वरित कार्रवाई से करीब 50 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना सेक्टर-66 और फेज-3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एक G+4 (ग्राउंड फ्लोर सहित चार मंजिला) इमारत में हुई, जिसका उपयोग पेइंग गेस्ट (PG) आवास के रूप में किया जा रहा था।प्रारंभिक जांच के अनुसार, आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर पर चार्ज हो रही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने से हुई। बैटरी से निकली चिंगारी ने पार्किंग में खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे पार्किंग क्षेत्र में फैल गई। आग के साथ उठे घने धुएं ने कुछ ही मिनटों में इमारत की ऊपरी मंजिलों को भी भर दिया, जिससे वहां रह रहे लोग अंदर फंस गए।घटना के समय इमारत में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कई निवासी अपनी जान बचाने के लिए बालकनी और खिड़कियों की ओर पहुंच गए और मदद के लिए आवाजें लगाने लगे। आसपास के स्थानीय लोगों ने भी तुरंत राहत कार्य में सहयोग किया और फायर विभाग को सूचना देने के साथ-साथ इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में प्रशासन की मदद की।घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। आग पर काबू पाने और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सात फायर टेंडर, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और विशेष बचाव वाहनों की मदद ली गई। दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इमारत में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और आग पर काबू पा लिया।गौतम बुद्ध नगर पुलिस के जॉइंट कमिश्नर राजीव नारायण ने बताया कि इमारत में पार्किंग ग्राउंड फ्लोर पर थी, बेसमेंट में नहीं। इसी कारण पार्किंग में लगी आग से निकला धुआं तेजी से सीढ़ियों और अन्य रास्तों से ऊपरी मंजिलों तक फैल गया। धुएं की वजह से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।पुलिस के मुताबिक, राहत और बचाव अभियान के दौरान अधिकांश लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि, दो लोगों की हालत धुएं के कारण गंभीर हो गई। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।फिलहाल पुलिस और फायर विभाग हादसे के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की प्रमुख वजह माना जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों को चार्ज करते समय सुरक्षा मानकों का पालन करने, चार्जिंग के दौरान निगरानी रखने और किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की अपील की है। साथ ही, बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच और आपातकालीन निकास व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर भी जोर दिया गया है।

कनाथ शिंदे की मुलाकात को 'चोरी की गई संपत्ति' को वैध बनाने का प्रयास बताया

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने बुधवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की और मुख्यमंत्री शिंदे पर चोरी की संपत्ति लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूमने का आरोप लगाया। उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली गए हुए हैं। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए राउत ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए और शिंदे गुट को मुंबई से दिल्ली ले जाया गया चुराया हुआ बंडल बताया। राउत ने कहा कि क्या इस देश में अभी भी कानून का राज है? एकनाथ शिंदे दिल्ली की सड़कों पर वह चीज़ लेकर घूम रहे हैं जिसे मैं 'चुराई हुई संपत्ति' कहता हूँ, फिर भी कानून उन्हें रोकता नहीं है। वे इस 'चुराए हुए बंडल' को मुंबई से देश के गृह मंत्री के पास ले गए हैं और कह रहे हैं, यह मेरी चुराई हुई संपत्ति है। कृपया इसे अपनी मंज़ूरी दें। अगर गृह मंत्री ऐसे कामों को मंज़ूरी देते हैं, तो मुझे कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर बहुत चिंता है। राउत की यह टिप्पणी 6 जुलाई को शिवसेना (UBT) के छह लोकसभा सांसदों—संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर—के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद आई है। इससे लोकसभा में उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों की संख्या घटकर तीन रह गई है, जो 2022 में पार्टी के बंटवारे के बाद से शिवसेना (UBT) के लिए एक बड़ा झटका है। राज्यसभा सांसद ने उद्धव ठाकरे से 'राम रक्षा' प्रार्थना का पाठ करवाने की BJP की मांग की भी आलोचना की और सत्ताधारी पार्टी से कहा कि वे इसके बजाय अयोध्या मंदिर में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर बात करें।

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में विवाद

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में एक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सभी हॉस्टल मेस में - जिनमें छात्रों द्वारा चलाई जाने वाली कोऑपरेटिव सुविधाएं भी शामिल हैं - नॉन-वेज खाना बनाने और परोसने पर रोक लगा दी है। यह फ़ैसला उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस में मांसाहारी खाना परोसे जाने पर चिंता ज़ाहिर करने के बाद लिया गया है। KGMU के मीडिया सह-प्रभारी कुमार शांतनु ने बताया कि यूनिवर्सिटी द्वारा चलाई जाने वाली मेस तो हमेशा से शाकाहारी रही हैं, लेकिन अब यह प्रतिबंध छात्रों द्वारा चलाई जा रही प्राइवेट मेस पर भी लागू होगा। शांतनु ने कहा कि KGMU कैंपस में लगभग 18 मेस चल रही हैं। गवर्नर को जानकारी मिली थी कि वहाँ मांसाहारी खाना पकाया और परोसा जा रहा था। KGMU द्वारा सीधे तौर पर चलाई जाने वाली मेस के बारे में यह बिल्कुल साफ़ है कि वहाँ कभी भी मांसाहारी खाना न तो पकाया गया और न ही परोसा गया। यह साफ़ किया गया कि ऐसा उन प्राइवेट या कोऑपरेटिव मेस में हो रहा था जिन्हें खुद छात्र चलाते हैं। गवर्नर की टिप्पणी के बाद, उन मेस में मांसाहारी खाना परोसने पर तुरंत रोक लगाने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। अगर इसके बाद कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी समाजवादी पार्टी ने इस प्रतिबंध की कड़ी आलोचना की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इस आदेश को तानाशाही बताया और किसी औपचारिक लिखित निर्देश के न होने पर सवाल उठाए। चांद ने कहा कि सरकारी कामकाज में आधिकारिक निर्देश ज़ुबानी नहीं दिए जाते। अगर कोई आदेश देना हो, तो वह लिखित रूप में होना चाहिए। लोगों को क्या खाना-पीना चाहिए, इस पर आदेश देना मनमाना और तानाशाही भरा फ़ैसला है। अगर KGMU यूनिवर्सिटी प्रशासन इसे मानता है, तो समाजवादी पार्टी का मानना है कि यह संविधान और कानून, दोनों का उल्लंघन है।

आस्था से जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्किल डेवलपमेंट मिशन और I.T. के तहत प्रशिक्षित युवाओं के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरन कहा कि साझा भविष्य तभी संभव है जब अवसर साझा किए जाएं। अवसर तब साझा किए जाते हैं जब सरकार की सोच वैसी हो। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा कार्यशक्ति है। मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभारी हूं कि उन्होंने 2014 में पदभार संभालने के बाद देश में कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना की। साझा भविष्य तब बनता है जब सरकार का दृष्टिकोण ऐसा हो। योगी ने आगे कहा कि दुर्भाग्य से, 2017 से पहले, राज्य सरकार खुद राज्य के लिए एक बुरा शगुन बन गई थी। उस समय, युवाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी, और कौशल विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं थे। असुरक्षा का माहौल था। सरकारी नौकरियों पर एक ही परिवार का एकाधिकार था। विपक्ष पर तंज कसते हुए योगी ने कहा कि वर्ष 2017 के पहले... सरकारी नौकरी पर एक खानदान का अधिकार था। नौकरी निकलती नहीं थी, निकल गई तो चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए भी निकल पड़ती थी। उन्होंने कहा कि यूपी का नौजवान यूपी में काम पाए, यह एक कल्पना थी। लेकिन अब यह साकार हो रही है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की घटना से हम जैसे राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है लेकिन इस मामले के बहाने अयोध्या और राम जन्मभूमि को बदनाम करना उचित नहीं है। 'इंडिया टुडे समूह' के कार्यक्रम "पंचायत आज तक" को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने पुराने रिकॉर्ड के बावजूद आस्था से जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या की घटना ने निश्चित रूप से हम सभी की, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाई है। 'राम मंदिर ट्रस्ट' एक स्वतंत्र संस्था है और सरकार को इसके मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ट्रस्ट ने जांच का अनुरोध किया और राज्य सरकार ने एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन किया।